



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ 1938 (श०)
(सं० पटना 586) पटना, सोमवार, 11 जुलाई 2016

सं० 2/आरोप-01-29/2014-सा०प्र०-9089

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

28 जून 2016

श्री कमलेश्वर गिरि (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 105/08, तत्का० निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव, कृषि विभाग सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध कृषि विभाग से प्राप्त फाईल/फोल्डर के आधार पर अपने पदस्थापन अवधि में रंगे हाथ घूस लेते पकड़े गये लोक सेवकों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा नहीं कर आरोपित लोक सेवकों को कम दंड देने अथवा बचाने का प्रयास करने संबंधी आरोप के लिए प्रपत्र 'क' गठित किया गया।

श्री गिरि के विरुद्ध आरोप है कि— श्री रामा शंकर सिंह, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नवादा द्वारा कृषि कार्य हेतु पावर टीलर अनुदान के लिए श्री संतोष कुमार, नवादा से 12,000/— रुपये रिश्वत लेते हुए दिनांक 11.12.2009 को निगरानी धावादल द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। श्री सिंह के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने संबंधी प्रतिवेदन पर इनके द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव दिया गया।

श्री रामाश्रय प्रसाद, तत्कालीन निरीक्षक माप—तौल, बांका भागलपुर को दिनांक 26.11.2008 को निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था तथा श्री प्रसाद के विरुद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन का भी आरोप प्रतिवेदित था, के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में मामले को संचिकास्त करने का प्रस्ताव दिया गया।

श्री रामसागर मिश्र, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, चकिया, मोतिहारी को 2000/- रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था, के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मिश्र के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया, परन्तु आरोपी कर्मों को लाभ पहुँचाने के लिए संचालन पदाधिकारी को बदलने का प्रस्ताव दिया गया। उक्त प्रस्ताव पर नियुक्त संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मिश्र के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया, जिसके आधार पर श्री मिश्र को इस शर्त के साथ आरोप मुक्त तथा निलम्बन मुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया कि फौजदारी मुकदमा के अंतिम आदेश पारित होने पर आरोप मुक्ति का आदेश तदनुसार प्रभावित होगा।

विभागीय पत्रांक 5278 दिनांक 16.04.2014 द्वारा श्री गिरि से उक्त प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री गिरि के पत्र दिनांक 13.05.2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

उल्लेखनीय है कि श्री गिरि दिनांक 30.06.2011 को सेवानिवृत्त हो गये। फलस्वरूप श्री गिरि के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8324 दिनांक 19.06.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

अपर विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक 86 दिनांक 18.02.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या 01 के संदर्भ में प्रतिवेदित किया गया है कि— “आरोप संख्या 01 में श्री गिरि के विरुद्ध इस हद तक प्रमाणित है कि उन्होंने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा नियम के अनुरूप प्रस्ताव नहीं दिये जाने के बावजूद अपने स्तर से सम्यक् समीक्षा नहीं करके उसी प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए वरीय पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया, परन्तु दिये गये साक्ष्यों के आधार पर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मों को बचाने की उनकी मंशा या संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है।” आरोप संख्या 02 एवं 03 में संचालन पदाधिकारी द्वारा अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय पत्रांक 3499 दिनांक 04.03.2015 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन पर श्री गिरि से अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री गिरि के पत्र दिनांक 26.03.2015 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्री गिरि के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से निम्न बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त की गयी :—

(i) आरोप संख्या :- 01— श्री रामाशंकर सिंह, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अकबरपुर, नवादा से संबंधित मामले में इनका यह कहना कि बिहार सेवा संहिता के नियमावली 74(बी) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव दिया गया है, मान्य नहीं हो सकता है। क्योंकि कृषि विभाग से प्राप्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री रामाशंकर सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही के आधार पर इस नियमावली के नियम 14 के प्रावधानों के तहत लघु एवं वृहत् शास्ति दिये जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जबकि बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान है। स्पष्ट है कि संचालित विभागीय कार्यवाही के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 14 के सुसंगत कंडिकाओं के प्रावधानों के तहत ही आरोपित पदाधिकारी को दंड दिया जाना है। इस प्रकार श्री गिरि का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

(ii) आरोप संख्या :- 02— श्री रामाश्रय प्रसाद, तत्कालीन निरीक्षक माप-तौल, बांका भागलपुर के विरुद्ध भी श्री गिरि द्वारा गलत प्रस्ताव उपस्थापित किया गया। श्री प्रसाद को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 26.11.2008 को रंगे-हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। तत्कालीन उप निदेशक (श्री हीरा तौती) द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि “आरोपी पदाधिकारी दिनांक 30.06.2010 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को उक्त नियमावली के नियम 14 में उल्लिखित दंड अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। श्री गिरि द्वारा इसी प्रस्ताव को निदेशक कृषि के अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया गया।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि श्री रामाश्रय प्रसाद की सेवानिवृत्ति के लगभग दो वर्ष पूर्व रंगे-हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। अतः श्री प्रसाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत परिवर्तित करते हुए विधि सम्मत् निर्णय लिया जा सकता था, जो कि श्री गिरि द्वारा नहीं किया गया।

(iii) आरोप संख्या :- 03— श्री रामसागर मिश्र के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मिश्र के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया था। आरोपी पदाधिकारी के अभ्यावेदन के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी को बदल कर अन्य पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनके द्वारा श्री मिश्र के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया जिसके आधार पर श्री मिश्र को इस शर्त के साथ आरोप मुक्त तथा निलम्बन मुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया कि फौजदारी मुकदमा के अंतिम आदेश पारित होने पर आरोप मुक्ति का आदेश तदनुसार प्रभावित होगा।

स्पष्ट है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मिश्र के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने की स्थिति में श्री गिरि द्वारा तथ्यों की सम्यक् समीक्षा नहीं की गयी मात्र संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष के आधार पर ही आरोप मुक्त किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है जिस कारण घूस लेते रंगे-हाथ पकड़े गये आरोपी पदाधिकारी को लाभ प्राप्त हुआ।

विभागीय पत्रांक 11128 दिनांक 03.08.2015 द्वारा उक्त असहमति के बिन्दुओं पर श्री गिरि को पुनः अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री गिरि के पत्र दिनांक 13.08.2015 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्री गिरि द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में कहा गया है कि उनके विरुद्ध तीन आरोप गठित किये गये थे, जिसमें गलत मंशा से तीनों आरोपियों को बचाने हेतु टिप्पणी देने का आरोप था। इस आधार पर संचालित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या 01 को आंशिक प्रमाणित एवं आरोप संख्या 02 एवं 03 प्रमाणित नहीं पाया गया। आरोप संख्या 01 के संदर्भ में इनका कहना है कि इनके द्वारा भी वृहत् दंड की अनुशंसा की गयी थी और विभाग द्वारा भी वृहत् दंड बर्खास्तगी का होना चाहिए, बताया गया जो वृहत् दंड की श्रेणी में ही आता है। श्री गिरि का कहना है कि सहायक से लेकर मुख्य सचिव तक टिप्पणी लिखना उनका दायित्व है और मेरे द्वारा उन दायित्वों का निर्वहन किया गया। अधीनस्थ की टिप्पणी को उचित मानने हेतु सक्षम प्राधिकार बाध्य नहीं है। अतः टिप्पणियों पर सरकार आरोपित नहीं करती है। दोष टिप्पणी देने वाले का नहीं है।

अन्य दो आरोपों के संदर्भ में इनका कहना है कि विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा आरोप संख्या 02 एवं 03 को प्रमाणित नहीं प्रतिवेदित किया है। विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग का ही एक भाग है, जिसमें सचिव स्तर के पदाधिकारी होते हैं।

श्री गिरि का कहना है कि जिन आरोपों के लिए उन्हें आरोपित किया जा रहा है, उन्ही टिप्पणियों को अनुमोदित करने वाले सक्षम प्राधिकार कृषि निदेशक को उन आरोपों के संचिकाओं का अवलोकन तथा समीक्षा के

पश्चात् राज्य सरकार ने विचारोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 14153 दिनांक 15.10.2014 के पत्र द्वारा संचिकास्त कर दिया गया।

साथ ही श्री गिरि द्वारा श्री रमेश झा (बि0प्र0से0), तत्कालीन उप कृषि निदेशक एवं श्री धनेश्वर चौधरी (बि0प्र0से0), तत्कालीन निदेशक (प्रशासन) का उदाहरण देते हुए इनका कहना है कि सदृश्य मामले में इन लोगों के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जाँच प्रतिवेदन से सहमत होकर सरकार द्वारा क्रमश संकल्प ज्ञापांक 10723 दिनांक 24.07.2015 एवं 3509 दिनांक 04.03.2015 द्वारा आरोप मुक्त करते हुए संचिकास्त कर दिया गया।

उनका कहना है कि भारतीय संविधान के धारा-14 मौलिक अधिकारों को प्रतिपादित करता है जिसमें समानता का अधिकार है। एक ही दोष के लिए अन्धों को मुक्त किया गया तथा मुझे आरोपित किया जा रहा है, जो कि उक्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री गिरि के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक् विचारोपरान्त पाया गया कि श्री धनेश्वर चौधरी, तत्कालीन निदेशक एवं श्री रमेश कुमार झा, तत्कालीन उप कृषि निदेशक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित करने के बाद अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप मुक्त/संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया था।

श्री चौधरी एवं श्री झा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी द्वारा श्री राम सागर मिश्रा से प्राप्त आपति के आलोक में गवाहों के प्रतिपरीक्षण का समुचित अवसर आरोपित पदाधिकारी को देने हेतु अन्य संचालन पदाधिकारी को नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया, लेकिन श्री गिरि के द्वारा पुनर्जाँच पश्चात् संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर सम्यक समीक्षा नहीं की गयी एवं आरोपित पदाधिकारी को आरोप मुक्त करने तथा निलंबन मुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया। इस आधार पर श्री रमेश झा एवं श्री धनेश्वर चौधरी के समान मामले होने के आधार पर श्री गिरि को आरोप मुक्त किये जाने का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

श्री गिरि का यह कहना कि टिप्पणी लिखना सहायक/पदाधिकारी का दायित्व है, दोष टिप्पणी देने वाले का नहीं बल्कि जो निर्णय लेते हैं, वह गलत निर्णय लेने के लिए दोषी होता है मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि वरीय पदाधिकारी होने के नाते श्री गिरि का यह दायित्व था कि विभागीय नियमों/निदेशों के आलोक में मामले की समीक्षा कर सही तथ्यों को सक्षम पदाधिकारी/अनुशासनिक प्राधिकार के समक्ष निर्णय हेतु उपस्थापित किया जाता, जो कि श्री गिरि द्वारा नहीं किया गया।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने जैसे गंभीर मामलों में सरकारी सेवकों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय नियमों/निदेशों के आलोक में समीक्षा नहीं करने, आरोपी पदाधिकारी/कर्मों को निलंबन मुक्त करने/आरोप मुक्त करने का प्रस्ताव देने तथा यथोचित दंड का प्रस्ताव नहीं देने तथा भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मों को बचाने में संलिप्तता संबंधी प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के प्रावधानों के तहत श्री गिरि के **“पेंशन से 10% की कटौती 10 वर्षों तक”** अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 3846 दिनांक 14.03.2016 बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 683 दिनांक 02.06.2016 द्वारा प्राप्त परामर्श में विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कमलेश्वर गिरि (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 105/08, तत्का० निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव, कृषि विभाग सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत "पेंशन से 10% की कटौती 10 वर्षों तक" का दंड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 586-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>